The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

A Serious & Genuine Institute For UPSC & BPSC

DAILY CURRENT AFFAIRS
For UPSC/BPSC

DATE : 25-08-2024

NOTE : Collect FREE copy of Monthly Current Afairs Magazine From our Centre

+91-84349 31877, +91-72506 67974

www.achieversiaspatna.co.in

achieversiaspatna@gmail.com

Orchid Mall, Boring Road (Opp: A.N. College) Patna 800001

सरकार के एनपीएस में वापस आने से सुनिश्चित पेंशन वापस आ गई है।

केंद्र सरकार ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू की। इससे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खत्म हो जाएगी।

यूपीएस लगभग पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) जैसी ही है। सरकारी कर्मचारियों से ओपीएस में वापस लौटने की मांग की जा रही थी।

यूपीएस की विशेषताएं:

- सुनिश्चित पेंशन - कर्मचारी अब पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पाने के पात्र होंगे।
- ओपीएस से अंतर यह है कि यूपीएस एक अंशदायी योजना होगी, जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% हिस्सा देंगे जबकि सरकार वेतन का 18.5% हिस्सा देगी। ओपीएस के तहत कर्मचारियों से कोई अंशदान की आवश्यकता नहीं थी।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:- कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी 60% पेंशन।

न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है - न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह। 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के पास दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया था। इसके तहत कर्मचारी के अंशदान को पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के माध्यम से बाजार और इक्विटी में निवेश किया गया था।

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को 60% राशि मिलेगी, जबकि 40% राशि फिर से निवेश की जाएगी। एनपीएस बाजार पर निर्भर था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा ओपीएस को वापस लाने की मांग की गई थी। कई गैर भाजपा राज्य ओपीएस में वापस चले गए थे।

ज़ेलेंस्की ने रक्षा और ड्रोन उत्पादन के क्षेत्र में भारत के साथ गठजोड़ करने पर विचार किया

यूक्रेनी प्रधानमंत्री व्लोदमीर ज़ेलेंस्की ने कृषि, साइबर सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च तकनीक के क्षेत्र में भारत के साथ अधिक सहयोग की वकालत की, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के सह-उत्पादन पर जोर दिया। दोनों देशों की ओर से जारी बयान में यह कहा गया।

भारत यूक्रेन के बड़े पैमाने पर माल का भंडारण करता है, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने यूक्रेन से रक्षा आयात कम कर दिया है और स्वदेशी रूप से उत्पादित माल का अधिक उपयोग कर रहा है।

कोलकाता मामले में सीबीआई ने 7 लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण शुरू किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को आर जी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले के सिलसिले में सात लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की।

पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष, अपराध से कुछ घंटे पहले पीड़िता के साथ भोजन करने वाले चार अन्य लोगों, सिविल पुलिस स्वयंसेवक संजय रॉय और एक अन्य सिविल पुलिस स्वयंसेवक पर यह परीक्षण किया जाएगा।

इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दे दी थी।

निकोबार परियोजना से स्थानीय जनजातियों को परेशान या विस्थापित नहीं किया जाएगा

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, महान निकोबार परियोजना के तहत बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास से शोम्पेन जनजातियों में से किसी को भी "परेशान या विस्थापित" नहीं किया जाएगा।

उन्होंने परियोजना पर चिंताओं के बारे में राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश को एक लिखित उत्तर में यह बात कही।

इस विकास से क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी कार्रवाई में भी मदद मिलेगी, म्यांमार के शिकारियों द्वारा समुद्री संसाधनों की चोरी पर अंकुश लगेगा, बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा किया जा सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

श्री यादव ने कहा कि परियोजना पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट नहीं बनाई गई क्योंकि यह परियोजना "रणनीतिक और रक्षा आयामों के साथ राष्ट्रीय महत्व" रखती है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्र वन भूमि होंगे, जो जनजातियों के स्वामित्व में नहीं हैं। जनजातियों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत 72,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरमहाद्वीपीय बंदरगाह, एक हवाई अड्डा, एक शहर और बिजली पैदा करने के लिए एक सौर संयंत्र बनाया जाएगा। इस परियोजना को गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि मलक्का जलडमरूमध्य को पार करने वाले जहाज यहां डॉक कर सकते हैं।

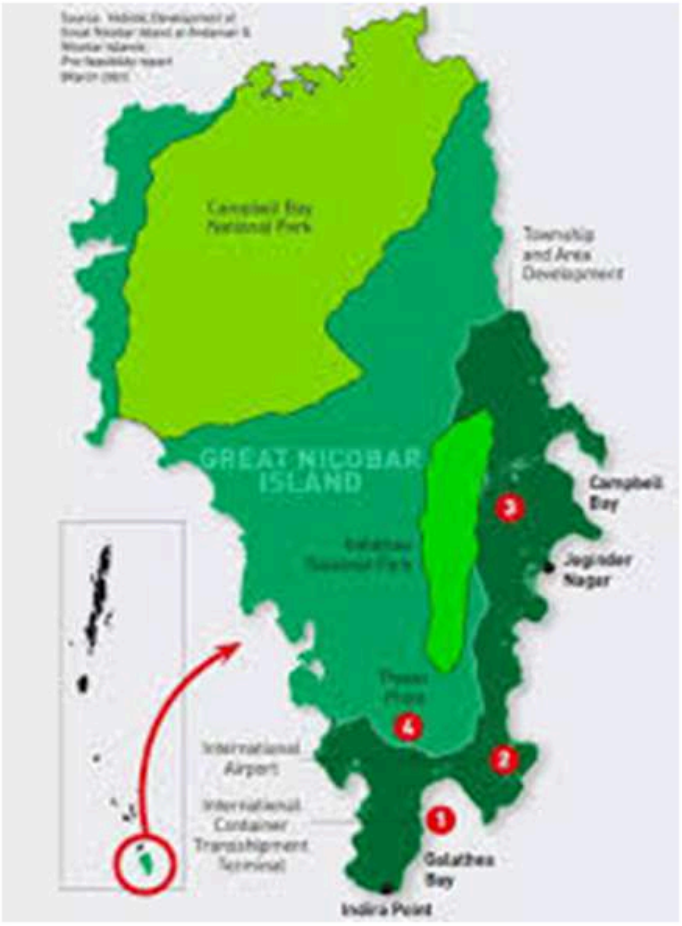

अमेरिका में, राजनाथ ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ रक्षा साझेदारी पर चर्चा की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में हैं। शुक्रवार को उन्होंने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट फोरम (यूएसईएस पीडीएफ) के तहत अमेरिकी रक्षा कंपनियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की।

भारत ने भारतीय नौसेना के एमएच 60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्लू) सोनोबॉय खरीदने का भी अनुरोध किया है, जिसे वर्तमान में 52.8 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से शामिल किया जा रहा है। इसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया जाना होगा।
दोनों देशों ने आपूर्ति सुरक्षा समझौते (एसओएसए) पर भी हस्ताक्षर किए। श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में विनिर्माण करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया है।

सोनोबॉय का उपयोग पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन्हें विमान के माध्यम से गिराया जाता है, इसका एक हिस्सा पानी के नीचे रहता है, जबकि एक हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। जो हिस्सा पानी के नीचे होता है वह पनडुब्बी का पता लगाने के लिए संकेत भेजता है और जो हिस्सा पानी के ऊपर होता है वह संभावित पनडुब्बी का पता लगाने के बारे में संकेत भेजता है।

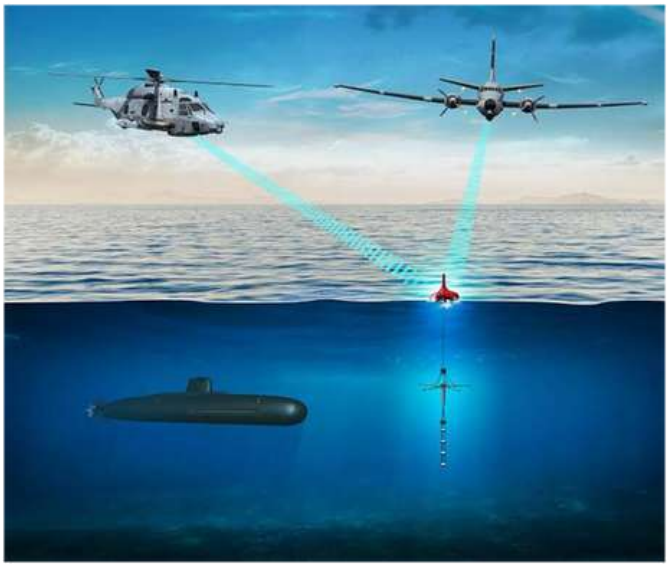

मार्च 2026 तक भारत वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा: अमित शाह

गृह मंत्री ने शनिवार को घोषणा की कि मार्च 2026 तक देश वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से मुक्त हो जाएगा, श्री शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की।

श्री शाह ने मुख्य सचिवों और डीजीपी की अंतरराज्यीय समन्वय की बैठक की घोषणा के बाद यह बात कही।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विकास, अभियोजन और एलडब्ल्यूई पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन के तीन मोर्चों पर लड़ रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 38 जिले एलडब्ल्यूई से प्रभावित हैं।

2019 और 2024 के बीच बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा नक्सलवाद से मुक्त हो गए।

महाराष्ट्र में यह अभी गढ़चिरौली जिले तक सीमित है।

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक नई आत्मसमर्पण नीति की घोषणा करेगी।उन्होंने नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों से हथियार डालने और विकास में सहयोग करने की अपील की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कर्मचारी के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नामक जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

वित्तीय परिव्यय की घोषणा अभी नहीं की गई है।

नीति के छह विषयगत कार्यक्षेत्र हैं: जैव आधारित रसायन और एंजाइम, कार्यात्मक भोजन और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु लचीला कृषि; कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग; समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रेस बयान में कहा गया है।

विश्व :

संघर्ष विराम वार्ता से पहले गाजा में इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए

गाजा में शनिवार को इजरायली हमले में 69 लोग मारे गए।

मरने वालों की संख्या 40,000 को पार कर गई है। युद्ध विराम उपायों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ काहिरा में बैठक कर रहे हैं, इसमें आईएस, मिस्र और कतर के अधिकारी शामिल हैं।

बांग्लादेश में बाढ़ के कारण तीन लाख लोग राहत केंद्र में हैं।

दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ के कारण करीब तीन लाख लोगों को आपातकालीन आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी है।

कोक्स बाजार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में समुद्र में फ्लेयर्स दागे: मनीला

फिलीपींस ने चीन पर हाल ही में दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास उसके एक गश्ती विमान पर फ्लेयर्स दागने का आरोप लगाया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता क्यों है?

अब तक की कहानी : कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच शुरू करने और उनकी पत्नी को मुआवजा भूखंड आवंटित करने में अनियमितताओं के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए जांच को मंजूरी दे दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिलहाल जांच पर रोक लगा दी है।

लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता क्यों है?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी या केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक बना दिया गया है।

सीआरपीसी की धारा 197 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भी यह एक आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल की भूमिका क्या है?

राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, इसलिए इस मामले में वे भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

हालांकि मुद्दा यह उठता है कि क्या राज्यपालों को मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर काम करना होगा।

अंतुले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल को खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। मौजूदा मामले में राज्य मंत्रिमंडल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जबकि राज्यपाल ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी।

लेटरल एंट्री नीति जांच के दायरे में क्यों है?

अब तक की कहानी : 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन दिया।

ऐसी भर्तियों के तहत कोटा लाभ की अनुमति नहीं है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस भर्ती को "राष्ट्र विरोधी कदम" करार दिया क्योंकि यह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण से दूर खुलेआम अराजकता थी।
20 अगस्त को यूपीएससी ने केंद्र के निर्देश के बाद विज्ञापन रद्द कर दिया।

लेटरल एंट्री के पीछे कारण : इसका एक कारण विशेष असाइनमेंट के लिए नई प्रतिभाओं को लाना है, इससे परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन में मदद मिलती है।
निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से कोई भी आवेदन कर सकता था। यह पद तीन से पांच साल की अवधि के लिए भरा जाना था।

क्या यह पहली बार था जब इस तरह की भर्ती की जा रही थी?

नहीं, 2019 से अब तक लेटरल रूट के ज़रिए 63 पद भरे जा चुके हैं. कम से कम सात लोगों ने बीच में ही अपनी नौकरी छोड़ दी.

नीति की शुरुआत कहाँ से हुई?

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लेटरल एंट्री भर्ती से सेवाओं में गतिशीलता आएगी.पिछली सरकार के दौरान भी ऐसी नियुक्तियाँ की गई थीं. मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया उन लोगों में शामिल थे जिन्हें बाहर से सरकार में शामिल किया गया था.

क्या हेमा समिति की रिपोर्ट से बदलाव आएगा?

अब तक की कहानी : 19 अगस्त को मलयालम फिल्म उद्योग में कई मुद्दों पर हेमा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई।

इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं का हवाला दिया गया है, क्योंकि यह उद्योग कुछ मलयालम निर्माताओं और निर्देशकों के चंगुल में है।

इस रिपोर्ट में जूनियर कलाकारों की खराब और अमानवीय स्थिति की ओर भी इशारा किया गया है।

सरकार ने हेमा समिति का गठन क्यों किया?

फिल्म उद्योग में एक महिला कलाकार के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद 17 फरवरी, 2017 को हेमा समिति का गठन किया गया था।

इस घटना के बाद केरल फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिला अभिनेत्रियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

इसके बाद केरल उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश के हेमा की अध्यक्षता में हेमा आयोग का गठन किया गया। समिति ने 2019 में केरल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

हाल ही में एक आरटीआई के तहत रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी मांगी गई। केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार को इसे सार्वजनिक करना पड़ा।

रिपोर्ट के निष्कर्ष : रिपोर्ट में "कास्टिंग काउच" के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, कास्टिंग काउच एक ऐसी प्रथा है जिसमें निर्देशक या निर्माता किसी महिला अभिनेत्री से फिल्म में भूमिका देने के बदले में यौन संबंध बनाने की मांग करते हैं।

पैनल ने उद्योग में काम करने वाली कई महिलाओं का साक्षात्कार लिया, उन्होंने अपने आरोपों की पुष्टि करने के लिए ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप और व्हाट्सएप संदेश प्रदान किए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग को पुरुष निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के एक शक्तिशाली समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें उन्होंने "माफिया" कहा है, क्योंकि वे किसी को भी उद्योग से प्रतिबंधित कर सकते हैं।

रिपोर्ट में जूनियर कलाकारों के लिए चेंजिंग रूम या शौचालय की सुविधा की कमी पर प्रकाश डाला गया है। जूनियर कलाकारों का वेतन कम है और उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति गुलामों जैसी हो जाती है।

समिति की सिफारिश क्या है?

समिति ने सिनेमा में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की। इसने फिल्म स्कूलों में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की।

राज्य सरकार ने रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन ने कहा है कि अगर पीड़ित शिकायत करने के लिए आगे आता है तो सभी मामलों में कार्रवाई की जाएगी। वह उन लोगों के बारे में बता रहे थे जिन्होंने समिति के समक्ष अपनी गवाही दी थी। केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

NEW BATCH FOR 71ST BPSC

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

FOUNDATION AND TARGET BATCH

HINDI & ENGLISH MEDIUM

BATCHES- ONLINE / OFFLINE

Starting From
26th August

www.achieversiaspatna.co.in

8434931877, 7250667974

Patliputra Colony,Near 181,Tennis Court, Opp: Awadhi, Aditya Vision.Patna. 800013